



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251 ]  
No. 251 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1997/आषाढ़ 3, 1919  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1997/ASADHA 3, 1919

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1997

सा.का.मि. 337(अ).—केन्द्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीली अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) “अपीली अधिकरण” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अपीली अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां :—समय-समय पर यथा संशोधित साधारण वित्तीय नियम, 1963 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 मूल नियम, पूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979, सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 की बाबत पीठासीन अधिकारी की वही शक्तियां होंगी जो किसी विभागाध्यक्ष को प्रदत्त की गई हैं।

परन्तु इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

[एफ 1(3)/96 डी.आर.टी.]

डी.आर.एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(Banking Division)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24 June, 1997

**G.S.R. 337(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);
- (b) "Appellate Tribunal" means the Debts Recovery Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (c) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of an Appellate Tribunal under section 9 of the Act;
- (d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Powers of the Presiding Officer of the Appellate Tribunal.—The Presiding Officer shall have the same powers as are conferred on a Head of Department in respect of the General Financial Rules, 1963, the Delegation of the Financial Powers Rules, 1978, the Fundamental Rules, the Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time :

Provided that the exercise of powers by the Presiding Officer under these rules shall be subject to such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

[F. 1(3)/96 D.R.T.]

D.R.S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1997

**सा.का.नि. 338( अ ).**—केन्द्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां :—समय-समय पर यथा संशोधित साधारण वित्तीय नियम, 1963 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 मूल नियम, पूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979, सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 की बाबत पीठासीन अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो किसी विभागाध्यक्ष को प्रदत्त की गई हैं।

परन्तु इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

[एफ 1(3)/96 डी.आर.टी.]

डी.आर.एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1997

**G.S.R. 338(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);
- (b) “Tribunal” means the Debts Recovery Tribunal established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) “Presiding Officer” means a person appointed as Presiding Officer Tribunal under section 4 of the Act;

- (d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Powers of the Presiding Officer of the Tribunal.—The Presiding Officer shall have the same powers as are conferred on a Head of Department in respect of the General Financial Rules, 1963, the Delegation of the Financial Powers Rules, 1978, the Fundamental Rules, the Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time :

Provided that the exercise of powers by the Presiding Officer under these rules shall be subject to such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

[F. 1(3)/96 D.R.T.]

D.R.S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

